‘अप्प दीपो भव’

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2017-18
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 31.12.2016
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज ;राम राजद्ध चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 20 ● अंक 3 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 16 से 31 दिसंबर, 2016

डॉ. उदित राज ने ट्वीट किया - क्रिकेट में हो आरक्षण

भेदभाव का हवाला देते हुए विनोद कांबली का जिक्र किया

नई दिल्ली 28 दिसंबर। अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन, डॉ. उदित राज भारतीय क्रिकेट में दलित वर्ग के लिए कोटे की मांग की है। डॉ. उदित राज के अनुसार, दलितों को इस खेल का हिस्सा बनने का पूरा अधिकार है और भारतीय क्रिकेट में दलितों के आरक्षण से भारत को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम मिलने में मदद मिलेगी। यही नहीं, डॉ. उदित राज ने अपनी इस मांग को जायज ठहराते हुए दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट में कोटा व्यवस्था का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में भी नस्लीय भेदभाव मिटाने के लिए क्रिकेट टीम में 11 में से करीब आधे अश्वेत खिलाड़ी रखे जाने का प्रावधान है।

जम्मू व कश्मीर की क्रिकेट टीम का चुनाव करते समय इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि 16 खिलाड़ियों में कभी जम्मू से 7 कश्मीर से 9 तो कभी जम्मू से 9 और कश्मीर से 7 खिलाड़ी चुने जाते हैं। जबकि हमारी राष्ट्रीय टीम में ऐसा कुछ नहीं है। एक ही शहर से सभी खिलाड़ी चुने जा सकते हैं। इससे अन्य क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अवसर नहीं मिलता।

विनोद कांबली स्वयं कह चुके हैं कि उनके साथ भेदभाव हुआ। उन्हें आज अपनी बात से मुकरने की बजाय और मुखर होकर कहना चाहिए। उन्हें सम्मान लेने के लिए मजबूती से खड़ा होना चाहिए। यह उनकी अकेले की लड़ाई नहीं है बल्कि आज देश के करोड़ों दलित उनके साथ हैं। यदि वे अपनी बात के साथ खड़े रहते तो कम से कम जो उनके साथ हुआ वह आने वाले समय में अन्य दलित युवाओं के साथ न होता।

गौरतलब है कि सचिन के बचपन के दोस्त विनोद कांबली को मास्टर ब्लास्टर की तरह ही प्रतिभावान माना जाता था। कांबली के करियर की शुरुआत तो धमाकेदार रही थी लेकिन वे टॉप स्तर के क्रिकेट की चकाचौंध में जल्द ही गुम होकर रह गए।

वर्ष 1971 में मुंबई में जन्मे विनोद गनपत कांबली ने अपने वनडे क्रिकेट करियर की शुरुआत 1991 में और टेस्ट क्रिकेट करियर की शुरुआत 1993 में की थी। वर्ष 2009 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। कांबली ने 17 टेस्ट मैचों की 21 पारियों में 54.20 के औसत से कुल 1084 रन बनाए, उनका अधिकतम स्कोर 227 रन रहा। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल चार शतक बनाए। वनडे क्रिकेट में कांबली ने 104 मैचों की 97 पारियों में 32.59 के औसत से कुल 2477 रन बनाए। वनडे क्रिकेट में दो शतक कांबली के नाम पर दर्ज हैं।

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंडुलकर का प्रदर्शन कम अच्छा होने के बावजूद उन्हें हुबली में मई 2016 में हुए अंतर क्षेत्रीय टूर्नामेंट में पश्चिम क्षेत्र की अंडर–16 टीम में चुना गया। एक पारी में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले दलित खिलाड़ी प्रणव धनावड़े के साथ भेदभाव हुआ और इस टीम में चयन नहीं हुआ, जबकि उनके अच्छे प्रदर्शन की प्रशंसा सचिन तेंदुलकर सहित कई राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने की थी। प्रणव के पिता एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं। जिस चयन समिति ने अंडर–16 टीम का चयन किया, उसमें समीर दीघे भी थे। दीघे सचिन तेंदुलकर के करीबी और शुभचिंतक के रूप में जाने जाते हैं।

थोरात कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भी अन्य जगहों के साथ–साथ दलित युवाओं के साथ खेलों में भयंकर भेदभाव है। इसके अनुसार फुटबाल, वालीवाल जैसे खेलों में मेहनती युवकों को अवसर मिल भी जाता है, क्योंकि ये मीडिया और उच्च

(शेष पृष्ठ 2 पर)

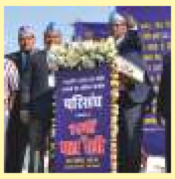

All India Parisangh @ AIParisangh
@Dr_Uditraj कांबली को दलित होने के कारण टीम से निकाला गया
m.indiatoday.instory/bjp-mp-u...

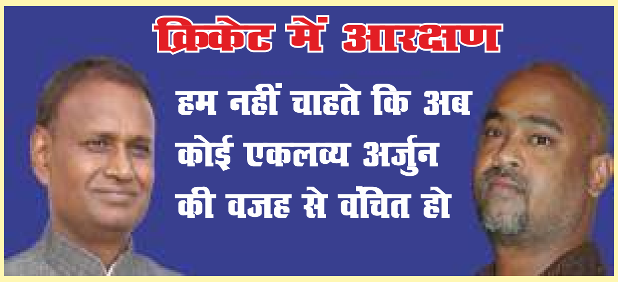

28/12/2016, 9:20 PM

Dr. Udit Raj, MP @Dr_uditraj
20 July 2009 @vinodkambli349
स्वीकार किया कि उनके साथ अन्याय हुआ उन्होंने चयनकर्त्ताओं को गलत साबित किया और अच्छा स्कोर बनाकर वापिसी की

Vinod Kambli @vinodkambli...
“श्रीमान राज, मैं आपके किसी बयान का सपोर्ट नहीं करता, इसलिए आप मेरे नाम का प्रयोग करने से परहेज करें

Dr. Udit Raj, MP @Dr_uditraj
@vinodkambli349 आपको शर्म नहीं करना चाहिए कि आप दलित हैं और यही कारण था कि आपको क्रिकेट टीम से निकाला गया
@BCCI @AIParisangh

Vikas Mogha @vikasmogha
@Dr_Uditraj @vinodkambli349
विनोद कांबली जी शिक्षित इलीट क्लास है, यह वास्तविकता का साथ दे और अपने बयान पर कायम रहे तो देश बदल सकता है।

आगामी 7 जनवरी को उ0 प्र0 के प्रांतीय सम्मेलन में होगा प्रदेश कार्यकारिणी का पुनर्गठन

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की उ0 प्र0 इकाई की बैठक आगामी 7 जनवरी, 2016 को प्रातः 11 बजे से कैपिटल सेन्टर, विधान सभा मार्ग,हजरतगंज, लखनऊ, उ0 प्र0 में निश्चित की गयी है। परिसंघ के सभी प्रदेश, जिला स्तर के पदाधिकारियों व पूरे प्रदेश के कार्यकर्त्ताओं से आग्रह है कि वे आवश्यक रूप से उपरोक्त बैठक में शामिल हों। अपनी उपस्थिति की अग्रिम सूचना राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, श्री संजय राज को मो. नं. 9654142705 व 9670552211 पर दे सकते हैं। मुझसे संपर्क न होने की स्थिति में कोई संदेश हो तो राष्ट्रीय कार्यालय में सुमित 9868978306 को लिखवा सकते हैं।

प्रांतीय इकाई को और अधिक शसक्त बनाने हेतु इकाई का पुनर्गठन भी उपरोक्त बैठक में होना है, इसलिए भी यह बैठक अतिमहत्त्वपूर्ण है। मैं स्वयं इस बैठक में उपस्थित रहूंगा।

डॉ. उदित राज,
राष्ट्रीय चेयरमैन

डॉ. उदित राज ने ट्वीट किया . . .

(पृष्ठ 1 का शेष)

वर्ग की नजर में कम आते हैं। क्रिकेट और हॉकी जैसे खेल जो मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं, इनमें दलित युवाओं के साथ ज्यादा भेदभाव होता है और इन्हें अवसर कम मिलते हैं।

डॉ. उदित राज ने कहा कि परिसंघ पूरे देश में सबसे बड़ा दलित संगठन है। हमारे पास तमाम योग्य खिलाड़ी आते रहते हैं। उनकी जोरदार सिफारिश भी करता हूं लेकिन उन्हें टीम में नहीं लिया जाता। मैं इस कदम के बारे में सोच रहा हूं ताकि हम भेदभाव का सामना कर सकें। जब काबिल और कुशल लोग हैं लेकिन मैं आश्वस्त नहीं हूं कि उनका चयन किया जाएगा और उन्हें खेलने का मौका मिलेगा। विनोद कांबली इसका एक उदाहरण हैं। भारत की 35 करोड़ आबादी में प्रतिभा को खोजना शुरू करना मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन होगा।

आज देश में समानता की बात की जाती है लेकिन जब अधिकारों और अवसरों की बात आती है तो दलितों के साथ भेदभाव देखने को मिलता है। चाहे वह व्यापार, नौकरी या खेल के क्षेत्र की बात हो। लोगों का यह मानना है कि क्रिकेट में तो सिर्फ प्रतिभावान युवाओं को ही मौका मिलता है। फिर क्रिकेट में आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। लेकिन कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि केवल ब्राह्मण या उच्च जाति के पास ही प्रतिभावान खिलाड़ी पैदा होते हैं क्या? यदि वर्तमान समय की भारतीय क्रिकेट टीम की बात की जाए तो भारत में केवल 4 प्रतिशत ब्राह्मणों में से 70 प्रतिशत भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और बाकी जाट, सिख, मुस्लिम व अन्य जातियों के खिलाडियों को मौका मिलता है। आखिर दलित खिलाडी ही पूर्णतयः क्यों गायब है? 80 वर्ष से अधिक क्रिकेट इतिहास में भारतीय क्रिकेट टीम से केवल 2 ही दलित खिलाडियों (कर्नाटक से बलवंत पालू और मुंबई से विनोद काम्बली) को मौका दिया गया है। क्या निम्न जाति में प्रतिभावान खिलाडी नहीं उत्पन्न होते है? यदि बलवंत पालू की बात की जाये तो वह बेहद ही प्रतिभावान खिलाड़ी थे लेकिन शानदार आंकडे होने के बावजूद उन्हें कभी कप्तान नहीं बनाया गया क्योंकि वह निम्न जाति के थे और ऐसा ही कुछ विनोद काम्बली के साथ भी हुआ। खुद क्रिकेट के जानकार यह मानते थे कि काम्बली सचिन से कहीं अधिक प्रतिभावान खिलाड़ी थे और उनके छोटे से क्रिकेट जीवन के आंकडे भी यही बताते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 50 से ऊपर की औसत जो कि उस समय में महान खिलाडियों से तुलना की जाने लगी थी। उन्हें भी पर्याप्त अवसर नहीं मिले और क्रिकेट का यह चमकता सितारा गायब हो गया। आज उदित राज ने एक बार फिर दलितों के लिए आवाज उठाई है इस लडाई में विनोद काम्बली को उदित राज का साथ देना चाहिए न कि भीगी बिल्ली बन सिर्फ दलितों का मजाक और अपमान देखना चाहिए ।

आओ नए वर्ष पर नए आंदोलन की शुरुआत करें

परिसंघ के सभी साथियों को नव वर्ष की शुभकमनाएं देते हुए आशा करता हूं कि 2017 में अवश्य ही सोसल मीडिया से जुड़कर नए आंदोलन की शुरुआत करेगें। आंदोलन के लगभग 20 वर्षों के अनुभव से हम लोग भलीभांति जान चुके हैं कि मनुवादी मीडिया हमारे आंदोलन की खबरें देते नहीं हैं और मीडिया के बिना आंदोलन सफल हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में अपना मीडिया बनाना ही एकमात्र विकल्प है। बड़े टी.वी. चैनल और बड़े अखबार चलाने की क्षमता हमारी है नहीं तो ऐसे में सोसल मीडिया ही एकमात्र विकल्प बचता है। इसलिए सभी साथियों से आग्रह है कि नीचे लिखे लिंक पर फेसबुक, ट्वीटर से जुड़े और अपने स्तर पर भी इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें।

fb.com/aiparisangh
twitter.com/aiparisangh
Whatsapp No.: 9899766443

विशेष -1 जनवरी 'शौर्य दिवस'

1 जनवरी 1818 "शौर्य दिवस"
"विजय स्तम्भ"

1 जनवरी को हम नववर्ष मनाते है आपस में बधाई देते है लेकिन 1 जनवरी बहुजन समाज के लिए ऐतिहासिक रूप से गौरवपूर्ण दिन है। हमारे समाज में बहुत ही कम लोग है जिनको यह बात मालूम है कि 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।

19वीं सदी के प्रारम्भ में पुणे के ब्राह्मण राजा वाजीराव पेशवा का शासन मनुस्मृति के कानून के आधार पर चलता रहा था। महाराष्ट्र की अछूत जातियों के साथ जाति–पाति, छुआ–छूत ही नहीं शारीरिक रूप से भी घोर अत्याचार किया जा रहा था। पेशवा की क्रूरता, उदंडता और नीचता ने सभी हदें पार कर डाली। कुछ अंग्रेज शासकों ने इन अत्याचारों को रोकने का प्रयास किया लेकिन कुछ राजा उनके गुलाम थे इसलिए वे ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे।

महाराष्ट्र की अंग्रेजी सेना में महार सैनिकों की एक महार रेजीमेंट थी। महार रेजीमेंट के महार सैनिक वाजीराव पेशवा के अत्याचारों से काफी कुपित थे और उनके अंदर उस अत्याचार को समाप्त करने की एक चिंगारी सुलग रही थी। संयोग से अंग्रेजों और पेशवा में किसी बात पर अनबन हुई अंग्रेजों द्वारा पेशवाओं के अत्याचारों से पीड़ित महार रेजीमेंट के चुनिंदा सैनकों को तैयार कर पेशवा को सबक सिखाने की योजना बनाई, महार सैनिकों को मनमांगी मुराद मिल गई। उनके दिमाग में पैट्रिक हेनरी के वे शब्द गूंज रहे थे कि ''अब हमें छुआ–छूत और जातीय अत्याचारों की गुलामी से मुक्ति चाहिए या फिर मौत।''

दिसम्बर माह 1817 में उन्होंने पेशवा पर हमला करने की एक अंतिम योजना बनाई। महार रेजीमेंट की लाइट इन्फैंट्री की 1 और 2 बटालियन तैयार हुई। अंग्रेजों ने उनकी पूरी मदद की थी। यह युद्ध अंग्रेजी कैप्टन फ्रांसिस स्टौनसन के नेतृत्व में लड़ा गया। कहते हैं कि ''यदि चार मैमनों का सेना पति शेर हो तो वे शेर की तरह लड़ते हैं, और सौ शेरों का सेनापति यदि कुत्ता हो तो सौ शेर कुत्तों की मौत मारे जाते हैं।'' यहाँ वही हुआ। एक तरफ दुनिया क्रिसमस का जश्न मनाने में मशगूल थी। दूसरी तरफ महार रेजीमेंट की बटालियन कमर कस के पेशवा की तरफ कूंच कर रही थी। सभी सैनिक भूख और प्यास के व अधिक पैदल चलकर काफी थके हुए थे लेकिन हौसलें आसमानी उड़ान भर रहे थे। वाजीराव पेशवा के पास एक बड़ी सैन्य ताकत थी। उसके पास 20 हज़ार सवार सैनिक और लगभग 10 हज़ार पैदल सैनिक थे। इतनी बड़ी शक्ति को नेस्तनाबूद करने के लिए मात्र 500 महार अछूत सैनिक अपने अधम्य साहस और हौसलें के बल पर तैयार थे।

1 जनवरी 1818 का दिन था। दुनिया नए साल के स्वागत के साथ जश्न मना रही थी और महार सैनिक नया इतिहास रचने का चक्रव्यूह रच चुके थे। यह युद्ध पुणे के कोरेगांव के उत्तर पश्चिम में भीमा नदी के तट पर लड़ा गया। 1 जनवरी 1818 को युद्ध हुआ क्रूर पेशवा की काली धरती को महार सैनिकों ने उन्ही के रक्त से लाल कर दिया था। महार सैनिकों ने पेशवा के लगभग 30 हज़ार सैनिकों की अटूट शक्ति को तोड़ कर रख दिया। वाजीराव पेशवा के सेना को महार सैनिकों ने सिर्फ धूल ही नहीं चटाई उनको धूल में मिला दिया और वाजीराव पेशवा को बंदी बना लिया। शूद्र वीरों की उस बहादुरी को देखकर अंग्रेजों ने भी दांतों तले ऊँगली दबा ली थी। 500 महार सैनिक बम्बई के मूलनिवासी थे।

इस युद्ध में मात्र 22 महार सैनिक शहीद हुए थे। दुनिया ने इस युद्ध के महार शूरवीरों के अधम्य साहस और वीरता के गीत गाये लेकिन भारत के मनुवादियों की आँखें सूज कर कुप्पा हो गयी। यह युद्ध भारत के इतिहास का एक जागीर या राज्य व रियासत जीतने का युद्ध नहीं था, यह युद्ध तो सदियों पुरानी जाति–व्यवस्था की जंजीरों को तोड़ने का अछूतों द्वारा हौंसलों के साथ किया गया एक संघर्ष था। इस घटना ने भारत की जाति–व्यवस्था की नींव हिलाकर रख दिया था। इस घटना से महात्मा ज्योतिबाराव फुले जैसे महान सामाजिक क्रांतिकारियों को एक बड़ी प्रेरणा मिली थी और उनके हौंसले बुलंद थे।

1851 में कोरेगांवमें अंग्रेजों ने 22 महार सैनिकों की याद में एक विजय स्तम्भ की स्थापना करवायी और वही महार सैनिकों की बहादुरी का जश्न मनाया था। वह स्तम्भ आज भी हमारे पूर्वज सैनिकों के जाति–व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष की गाथा सुनाता हुआ हमें प्रेरणा देता है।

हमारे 22 बहादुर शहीद महार सैनिकों को श्रद्धांजलि देने और इस घटना के आधार पर ही पूरे देश में से मनुवादी राज को समाप्त करने के लिए प्रेरणा सन्देश देने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जी भी कोरेगांव जाया करते थे। इस दिन बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर अछूतों को सम्बोधित करते हुए कहते थे कि आज संकल्प लो कि इसी तरह संघर्ष करके हम पूरे देश में से ब्राह्मण राज को समाप्त करेंगे। वे सभी शूद्रों को समझाते थे कि हमें ब्राह्मण से लड़ने के लिए अस्त्र–शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है बल्कि एक साहस और हौसले और संकल्प की जरुरत है।

बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने 1927 में कोरेगांव में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया और लोगों को अछूत महार सैनिकों के अधम्य साहस और वीरता की याद दिलाई। बाबा साहेब ने कहा 1 जनवरी को हम नए साल के जश्न के रूप में मास, मदिरा, पान और नाच–कूद कर न मना कर अपने बहादुर शूद्र सैनिकों के शौर्य दिवस के रूप में प्रेरणा के लिए मनाया करें।

आज भी हमारे समाज के लोगों के अंदर कमी है तो साहस और हौसले की, प्रेरणा की। हमारे लोग अपना इतिहास भूल गए वह आज टी. वी. पर प्रसारित भजन सुनने में व्यस्त रहते हैं, काल्पनिक कहानियों पर आधारित कार्यक्रमों को देखने में मस्त रहते हैं। आज बाबा साहेब के आशीर्वाद से हमारे समाज के लोग पढ़–लिख गए हैं लेकिन दुःख की बात यही है कि वे अपने पूर्वजों का इतिहास कभी नहीं पढ़ते। किसी ने कहा भी है कि 'किसी समुदाय का अस्तित्व समाप्त करना है तो उसके इतिहास को नष्ट कर दो, वह समुदाय स्वतः नष्ट हो जायेगा।' आज हमारे लोग फिर मानसिक रूप से गुलाम हो रहे हैं। वे अपने महापुरुषों के बलिदानों को भुला रहे है जिनसे हम साहस और प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं।

जय भीम ! नमो बुद्धाय !!

28 नवंबर की रैली के उपरांत प्रधानमंत्री महोदय को सौंपा गया ज्ञापन

28 नवंबर, 2016

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
रायसिना हिल, साथउ ब्लाक
नई दिल्ली

महोदय,

आज भारी संख्या में पूरे देश से अजा/जजा कर्मचारी–अधिकारी एवं समर्थक नई दिल्ली के रामीलाला मैदान में अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के तत्वावधान में अपने संवैधानिक अधिकार और देश की प्रगति के लिए एकत्रित हुए।

अजा/जजा को दिए जाने वाले आरक्षण को अक्सर आर्थिक विकास में बाधक कहा जाता है और साथ ही प्रशानिक दक्षता में भी बाधक माना जाता है। आरक्षण का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ था। सन् 1902 में शाहू जी महाराज ने कोल्हापुर रियासत में आरक्षण लागू किया। सन् 1921 में जस्टिस पार्टी की सरकार ने मद्रास खंड (जिसमें आज का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि आते थे) में आरक्षण लागू किया। मैसूर प्रदेश में 1921 और बांबे खंड में 1931 में आरक्षण लागू किया गया। त्रावणकोर के महाराजा ने 1935 में आरक्षण लागू किया और उसके बाद कोचीन में भी यह लागू हुआ। आज तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण है। अगर सभी प्रदेशों के बीच तुलना की जाए तो तमिलनाडु देश के अच्छे प्रशासनिक राज्यों में से एक है। आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के पैमाने में दक्षिण भारत के प्रदेश अक्सर उत्तर भारत के प्रदेशों से बेहतर पाए गए हैं। सन् 1943 में भारत सरकार ने पहली बार आरक्षण लागू किया। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह निष्कर्ष सही है लेकिन यह जरूर प्रतीत होता है कि जहां शासन और प्रशासन में भागीदारी ज्यादा है, वे प्रदेश बेहतर कर रहे हैं।

सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व यह जानता है कि आप मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, क्लीन इंडिया आदि का बिगुल बजा चुके हैं। अजा/जजा की आबादी पूरे देश की आबादी का लगभग एक चौथाई है और इनको औद्योगीकरण एवं प्रगति से अलग–थलग रखने का अर्थ है कि इनकी क्रय शक्ति कम करनी, जिसका आर्थिक प्रगति पर भी असर पड़ता हैं। औद्योगिक क्षेत्र के तेजी से विकसित होने का कारण भारत की जनसंख्या है। अगर अन्य पिछड़ों की भी गिनती की जाए तो भारत में 80 प्रतिशत लोग आरक्षित वर्ग में आते हैं। आरक्षण की वजह से उनका मनोबल बढ़ता है और क्रयशक्ति भी बढ़ती है, जिसका सीधा असर भारत के विकास पर पड़ता है। शासन व अन्य क्षेत्रों में इनकी भागीदारी से ये भी उद्यमी बनेगें और अपना कारोबार शुरू कर पाएंगें, जिससे कि भारत देश भी मजबूत होगा और जी.डी.पी. भी बढ़ेगा।

हॉल में 500 और 1000 रूपये की नोटबंदी की वजह से सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के पास रिकार्ड तोड़ राशि जमा हुई है। कई सरकारी सूत्रों ने कहा है कि इसकी वजह से सस्ती ब्याजदर पर कर्ज मिलेगें। ऐसे हालात में भारत सरकार को एक लाख करोड़ रूपये की लागत से एक सार्वजनिक अजा/जजा बैंक की स्थापना करनी चाहिए, जैसे महिला बैंक की स्थापना हुई। इससे कम ब्याजदर पर अजा/जजा वर्ग के उद्यमियों को कर्ज मिलेगा और भारत सरकार को स्टैंडअप इंडिया योजना को सफल करने का अवसर मिलेगा।

निजीकरण के शुरूआत से अजा/जजा वर्ग के लोग शासन–प्रशासन से ही नहीं, परन्तु आर्थिक कार्यों से भी वंचित हो रहे हैं। इस वंचित होने का एक अहम कारण देश की न्याय प्रणाली है। बेरहमी से विधायिका द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को न्यायपालिका छीन लेती है। उदाहरण के तौर पर 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधन वाजपेयी सरकार लायी थी। 85वां संवैधानिक संशोधन पदोन्नति में आरक्षण के लिए किया गया था, जिसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी और 2006 में इसका निर्णय आया जो नागराज केस के नाम से जाना जाता हैं। पांच जजों की पीठ ने इस संवैधानिक संशोधन को वैध माना था लेकिन इसमें कुछ अनुचित शर्ते भी लगा दी थी, जैसे – पर्याप्त प्रतिनिधित्व, पिछड़ापन और प्रशासनिक दक्षता पर असर न पड़ता हो। जहां तक पिछड़ेपन का सवाल है, यह तभी साबित हो जाता है, जब अजा/जजा वर्ग के लोगों को संविधान की धारा 341 और 342 के तहत लाया जाता है, जिसका परीक्षण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग द्वारा किया जाता है।

लखनऊ उच्च न्यायालय ने 4 जनवरी, 2011 को उ0 प्र0 में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया। उस समय की प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की, जिसने दो जजों की उच्च न्यायालय के फैसले को वैध ठहराया। न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार छोटी पीठ, बड़ी पीठ के फैसले को अवैध नहीं ठहरा सकती लेकिन इस मामले में ऐसा ही हुआ। दिसंबर, 2012 में राज्य सभा में पदोन्नति में आरक्षण का बिल पास किया गया ताकि न्यायपालिका की विसंगतियों को दुरूस्त किया जा सके, पर यह बिल लोक सभा में पास नहीं हो पाया। उ0प्र0 की समाजवादी सरकार के आतंक में हजारों दलित कर्मचारियों की पदावनति हो रही है। चीफ इंजीनियर को एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाया जा रहा है और इस फैसले से लोग इतने निराश हैं कि दलित कर्मचारी–अधिकारी कार्यालय नहीं जाना चाहते क्योंकि अभी तक जो अधिकारी उनके नीचे कार्य करता था वह उनसे सीनियर हो गया है। भेदभाव की हद तो तब पार हो गयी जब सामान्य योग्यता पर भर्ती हुए अधिकारियों को भी दलित होने के नाते पदावनत किया गया है। हाल ही में जबलपुर के उच्च न्यायालय ने भी ऐसा ही एक फैसला सुनाया है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में भी ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है। इस तरह से सारे फैसले अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता का प्रतीक हैं और भारत के संविधान की आत्मा के खिलाफ हैं। मैं भारत सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि लोक सभा के इसी सत्र में पदोन्नति में आरक्षण बिल पास किया जाए, ताकि दलितों और आदिवासियों को इस इस क्रूरता एवं भेदभाव से बचाया जा सके।

महोदय, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, देशवासियों में आशा की एक नई किरण जागी है। अनुसूचित जाति /जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, जिसका मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूं, यह पहली संस्था है, जिसने निजी क्षेत्र में सबसे पहले आरक्षण की मांग की थी। यूपीए सरकार ने 2004 में मंत्रियों की एक समिति निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए गठित की थी, इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में भी कोर्डिनेशन कमेटी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में अधिकारियों की एक समिति गठित की थी, पर ये गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। सरकार पर निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए दबाव बनता हुआ देख फिक्की, एसोचेम एवं सीआईआई जैसी उद्योगपतियों की संस्थाओं ने सरकार से दरख्वास्त की कि उन पर आरक्षण थोपा न जाए बल्कि वे स्वयं दलितों को उद्यमी बनाने के लिए कोचिंग, ट्यूशन एवं ट्रेनिंग इत्यादि प्रदान करेगें, पर उन्होंने यह वायदा भी नहीं निभाया। पिछली सरकार ने दलितों और आदिवासियों को सरकारी खरीद में भागीदारी देने की बड़ी बातें की। उन्होंने यह कानून भी बनाया कि सरकारी विभाग, मंत्रालय और केन्द्र सरकार की संस्थानों में 4 प्रतिशत खरीदारी दलितों के लघु उद्योगों से हो। पर यह भी न सफल हो पाया। आज सिर्फ .5 प्रतिशत ही खरीद दलितों के लघु उद्योगों से की जा रही है। सरकार को इस विषय में शक्ति बरतने की जरूरत है, ताकि 4 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा हो सके। मेरी आपसे आग्रह है कि आप इस विषय में ठोस कदम उठाएं।

रक्षा अधिग्रहण में मल्टीप्लायर ऑफसेट पॉलिसी लागू है, जिसके अंतर्गत कम से कम 10 प्रतिशत अधिग्रहण फॉरेन डारेक्ट इन्वेस्टमेंट जजा/जजा वर्ग के लघु उद्योगों से हो, ऐसा ही नियम बाकी क्षेत्र जैसे रेलवे, ऊर्जा, खान, उड़ान आदि क्षेत्रों में भी लागू हों और मल्टीप्लायर ऑफसेट प्रोविजन भी बढ़ाया जाए ताकि अजा/जजा वर्ग के लघु उद्योग विश्वस्तरीय पुर्जे बना पाएं।

काफी दुविधा है कि उच्चतम न्यायालय ने 99वां संवैधानिक संशोधन अवैध ठहराया, जिससे कि नेशनल ज्यूडिशियन एप्वाइंटमेंट कमीशन की स्थापना नहीं हो पाई। पूरे विश्व में कहीं भी जज स्वयं जज की नियुक्ति नहीं करते। भारत ही इस विषय में एक ऐसा अनोखा देश है। मैं पुनः सरकार से आग्रह करता हूं कि संविधान में संशोधन किया जाए और न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका में समानता बरकरार रहे। यह उम्मीद करना बिल्कुल ही गलत है कि हाल में प्रचलित कोलेजियम सिस्टम में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को भागीदारी मिलेगी। ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस की स्थापना के पक्ष में चीफ जस्टिस कांफ्रेंस ने 1961, 1963 और 1965 में बयान दिया। भारत सरकार ने 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में पास किया लेकिन इसे भारत सरकार के राजपत्र में नहीं लाया गया और न ही इस संशोधन का अभी प्रयोग किया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1991 में आदेश दिया था कि ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस की स्थापना की जाए और इस विषय में उपयुक्त कदम उठाने हेतु भारत सरकार को आदेश दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने भी यह कहा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जैसे संवैधानिक संस्थान आरक्षण से बच नहीं सकते। इसी तरह का दूसरा आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2016 में दोहराया। मैं भारत सरकार से विनती करता हूं कि ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस की स्थापना में और विलंब न हो और इस सर्विस में अजा/जजा, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं की भूमिका अहम रखी जाए, जैसा कि वर्तमान समय में नहीं है।

यदि माना जाए कि आरक्षण शासन में भागीदारी के लिए है तो एससीपी एवं टीएसपी गरीबी उन्मूलन और विकास के लिए हैं। एससीपी एवं टीएसपी के सिद्धांत के अनुसार आरक्षण प्रतिशत के अनुसार बजट में भी भागीदारी होनी चाहिए। जरूरत के अनुसार कभी भी फंड आबंटित नहीं किया गया और जितना आबंटित किया गया, वह भी अजा/जजा वर्ग के विकास में नहीं लगाया गया। इसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि व्यक्तिगत या पारिवारिक विकास के लिए सीधा इन पैसों का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन यह कभी होता नहीं। अक्सर यह देखा गया है कि एस.सी.पी. एवं टी.एस.पी. का फंड सार्वजनिक कार्यों में लगाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। हमेशा से यह मांग रही है कि केन्द्र, प्रदेश और जिला स्तर पर कमेटियां गठित हों, जो एससीपी, टीएसपी फंड के लिए योजना बनाएं और उनकी निगरानी भी करें। इसलिए मैं मांग करता हूं कि आगामी वर्ष में एससीपी एवं टीएसपी के फंड उनके उद्देश्यों के अनुसार आबंटित और खर्च हों।

महोदय, शिक्षा ही एकमात्र ज़रिया है, जिससे कि मानव संसाधन की कल्पना की जा सके। दुखद बात यह है कि अक्सर अजा/जजा वर्ग के छात्र सरकारी स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि वे निजी क्षेत्र में गुणवत्ता वाली शिक्षा का खर्च नहीं वहन कर पाते। सरकार ने सर्वशिक्षा का कानून तो लागू किया लेकिन गुणवत्ता के बिना यह बेकार है। यह भी देखा गया है कि छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ाई गयी है, जिसकी वजह से काफी छात्र शिक्षा का खर्च नहीं वहन कर पा रहे हैं। लंबे अर्से से अजा/जजा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास एवं स्कूल निर्माण का कार्य लंबित है, जबकि यह कार्य और तेजी से होना चाहिए था।

संविधान की धारा 370 की वजह से जम्मू व कश्मीर के अजा/जजा वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। इसका कारण यह है कि आरक्षण कानून संसद से पास होने के बाद भी जम्मू एवं कश्मीर विधान सभा से पास हुए बिना यह कानून वहां लागू नहीं हो पाता। इस कारण से 77वां, 81वां एवं 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधन जम्मू व कश्मीर में लागू नहीं है, जिसकी वजह से लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अपने हक भी खोने पड़ रहे हैं। यदि प्रदेश सरकार भारतीय संसद के कानून मानने को तैयार नहीं तो कम से कम उन्हें अपनी विधान सभा का आरक्षण कानून 2004 को लागू करना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जम्मू एवं कश्मीर की सरकार को यह निर्देश दें कि अजा/जजा वर्ग के हक छीनना बंद करे।

भारतीय सेना के चमार रेजीमेंट को 1946 में बंद कर दिया गया, जबकि जाति आधारित अन्य रेजीमेंट जैसे जाट, राजपूत आदि अस्तित्व में हैं। सिर्फ चमार रेजीमेंट को ही क्यों बंद किया गया ? यदि रक्षा मंत्रालय ने इस उद्देश्य से बंद किया कि जाति आधारित रेजीमेंट नहीं होनी चाहिए तो जाट एवं राजपूत रेजीमेंट को भी तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। यदि यह विचार नहीं है तो

(शेष पृष्ठ 4 पर)

दिल्ली के सभी जोनों की बैठक हुई

दलित विकास, राष्ट्र विकास
इस लड़ाई में अपना पूरा योगदान दे।
AIParisangh.com
AIParisangh
AIParisangh
9899766443

28 दिसंबर, 2012 को राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ0 उदित राज ने अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय पिरिसंघ की दिल्ली के सभी 25 जानों की बैठक बुलाई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारियों ने भाग लिया। 28 नवंबर को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में आयोजित रैली से पूर्व पूरी दिल्ली को अपनी सुविधानुसार से 25 जोनों में विभाजित किया गया। ये सभी जोन परिसंघ के पदाधिकारियों ने अपने हिसाब से बनाए। इसके लिए सरकारी मानचित्रों और जिले इत्यादि का सहारा नहीं लिया गया। कई बार एक जिले में कई जोन बनाए जा सकते हैं तो कभी अपनी सुविधानुसार कई जिलों को मिलाकर एक जोन भी बनाया जा सकता है। परिसंघ के सक्रिय कार्यकर्त्ताओं की संख्या इत्यादि को मद्देनजर रखते हुए इनका विभाजन किया गया। एक जोन में एक अध्यक्ष एवं दो–तीन प्रमुख पदाधिकारी बनाए गए। इसके बाद यह देखा गया कि कार्य बहुत ही आसान हो गया। रैली हेतु राष्ट्रीय कार्यालय ने सिर्फ जोन के प्रमुखों और वरिष्ठ पदाधिकारियों को ही सम्पर्क किया और आगे का कार्य जोन के पदाधिकारियों ने स्वयं किया। दिल्ली में एक प्रयोग के तौर पर ऐसा मॉडल तैयार किया गया। अब पूरे देश में इसी प्रकार से इकाइयों को विभाजित करके कार्य करने की योजना है।

बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. उदित राज ने आए हुए सभी पदाधिकारियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि 2017 में हमें नई नीतियों के साथ आंदोलन की शुरुआत करनी है। उन्होंने कहा कि मनुवादी मीडिया प्रायः हमारे आंदोलन की अनदेखी करती है। इतनी बड़ी रैली को मीडिया ने उचित जगह नहीं दिया जबकि मेरे द्वारा किए गए कुछ ट्वीट को मीडिया ने विवादित बनाकर कई दिनों तक सुर्खियों में रखा। इनके लिए इतनी बड़ी–बड़ी रैलियों के माध्यम से उठाई गयी मांगें कोई मायने ही नहीं रखती। कोई भी आंदोलन मीडिया के सहयोग के बिना सफल हो नहीं सकता और मनुवादी मीडिया हमें जगह देती नहीं तो ऐसे में सोसल मीडिया के माध्यम से अपनी मीडिया बना अति आवश्यक हो गया है। आशा की जाती है कि 2017 में जो साथी यहां बैठे हैं वे तो सक्रिय रूप से सोसल मीडिया का इस्तेमाल करेगें ही, उन लोगों को भी इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करेगें जो यहां पर उपस्थित नहीं हैं।

इस तरह से 2017 में सोसल मीडिया का सहारा लेकर अपने आंदोलन को कई गुना अधिक गति देना है।

The All India Parisangh,under the leadership of Dr. Udit Raj, was formed in 1997 to fight against 5 anti reservation orders. You can contribute your bit in this battle by becoming a member of the Parisangh at www.aiparisangh.com . You can also be updated regularly of the achievements and activities on the Parisangh's social media accounts.
Like us :
www.Facebook.com/aiparisangh
Follow us:
www.Twitter.com/aiparisangh
Email us : Info@aiparisangh.com
Whatsapp us : 9899766443

28 नवंबर की रैली के उपरांत प्रधानमंत्री ....

(पृष्ठ 3 का शेष)

भारतीय सेना में दलितों की भागीदारी के लिए चमार रेजीमेंट के साथ–साथ बाल्मीकि, खटीक, धानुक, धनगड़ इत्यादि रेजीमेंट का अतिशीघ्र गठन किया जाए।

निजीकरण ने ऐसे शोषण का रूप धारण कर लिया है, जो कि विश्व में शायद ही अन्यत्र देखने को मिलता है। चौथी श्रेणी की लगभग सभी भर्तियां ठेके पर की जा रही हैं, जहां वेतन तो कम है ही, ये वेतन भी मजदूरों को पूरा नहीं दिया जाता। ठेकेदारी प्रथा को तुरंत बंद करना चाहिए और जहां यह प्रथा चल रही है, वहां सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये देखें कि मजदूरों का वेतन बिना कटौती के उनके बैंक खातों में जमा हो। इस ठेकेदारी प्रथा के सबसे ज्यादा शिकार सफाई कर्मचारी हैं।

एक प्रदेश से बना जाति प्रमाण–पत्र को सभी प्रदेशों में मान्यता मिले। खाली पड़े पदों को विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरा जाए। दिल्ली में 20 सूत्रीय कार्यक्रम में आबंटित जमीन के मालिकों को 30–40 साल बाद भी मालिकाना हक नहीं दिया गया है। दिल्ली के मंत्रिमंडल द्वारा मालिकाना हक प्रदान करने के लिए मंजूरी दे दी गयी है परन्तु यह मामला अभी भी गृहमंत्रालय में लंबे समय से लंबित है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि सरकार इन्हें अतिशीघ्र मालिकाना हक दिलाए।

शारांश

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की मुख्य मांगों पर रैली में भाग लेने वाले सभी लोगों ने प्रस्ताव पास किया, जिनका दुबारा नीचे उल्लेख किया जा रहा है।

1. पदोन्नति व निजी क्षेत्र में आरक्षण
2. आरक्षण कानून बनाओ
3. जाति आधारित जाट, राजपूत आदि की तरह चमार रेजीमेंट के साथ–साथ माला–मादिगा,
   बाल्मीकि, खटीक, धनगर आदि रेजीमेंट भी बनाकर सेना में भागीदारी सुनिश्चित हो
4. साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में 6 अश्वेत के कोटे की तर्ज पर भारत में
   भी दलितों–आदिवासियों व पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए।
5. दिल्ली सरकार लाखों कर्मचारियों को पक्का करे
6. सेना और उच्च न्यायपालिका में आरक्षण
7. सफाई काम में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना
8. बैकलॉग पदों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान
9. समान शिक्षा एवं भूमिहीनों को भूमि
10. अनुसूचित जाति योजना एवं जन जाति उप योजना कानून बनाओ
11. एक राज्य का जाति प्रमाण–पत्र सभी राज्यों में मान्य हो
12. महंगाई की दर से छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी
13. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन और उसमें आरक्षण
14. जम्मू व कश्मीर में धारा 370 हटाया जाए और आरक्षण लागू हो
15. दिल्ली में 20 सूत्रीय कार्यक्रम में आबंटित भूमि का मालिकाना हक
16. एससी/एसटी बैंक की स्थापना एक लाख करोड़ रूपये की राशि से हो

महोदय, मैं, पूरे देश से आए परिसंघ के पदाधिकारियों जैसे – ब्रह्म प्रकाश, परमेन्द्र, रवीन्द्र सिंह, एन. डी. राम, रामनंदन राम (दिल्ली), धर्म सिंह, केदारनाथ, सुशील कमल, नीरज चक, निर्देश कुमारी (उ.प्र.), सिद्धार्थ भोजने, दीपक तभाने, संजय कांबले, सुनील जोडे, सिद्धार्थ कांबले, सूर्यकांत किवांडे (महाराष्ट्र), एस.पी. जरावता, डॉ. मुख्तियार सिंह, महासिंह भूरानिया (हरियाणा), तरसेम सिंह, दर्शन सिंह चंदेढ़, रोहित सोनकर (पंजाब), विश्राम मीना, रंजीत मीना, एम.एल. रासु, मुकेश मीना (राजस्थान), हरिश्चंद आर्या (उत्तराखंड), आलेख मलिक, डी.के. बेहरा (उड़ीसा), परमहंस प्रसाद, नरेन्द्र कुमार (म.प्र.), रामूभाई वाघेला, एन.जे. परमार, (गुजरात), एस. करुपइया, पी.एन. पेरुमल (तमिलनाडु), के. कृष्णन कुट्टी, बाला कृष्णन (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), के. महेश्वर राज, प्रकाश राठौर, जे. बी. राजू (तेलंगाना), डॉ. श्याम प्रसाद (आंध्र प्रदेश), अनिल मेश्राम, हर्ष मेश्राम (छ.ग.), कमल कृष्ण मंडल, सुबराता बातूल, रामेश्वर राम, सपन हलदर, पी. बाला (प. बंगाल), मधुसूदन कुमार, दिनेश कुमार, बी. एन. प्रसाद, एल.एम. ओरांव (झारखंड), आर.के. कलसोत्रा (जम्मू व कश्मीर), मदन राम, कुमार धीरेन्द्र, शिवधर पासवान (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, चन्नप्पा (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि.प्र.), प्रदीप बास्फोर (असम) के साथ आपके विचारार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु यह सौंप रहा हूं।

सधन्यवाद,
आपका,
(डॉ. उदित राज)

झारखंड प्रदेश परिसंघ का एकदिवसीय सम्मेलन

UNITED BANK OF INDIA
SC/ST Employees' Welfare Council
16th All India ... General
10th Dec. 2016
... Bhagwan Birsa Munda Nagar, Fr. CDM Auditorium
St. Xavier's College, Ranchi, Jharkhand

10 दिसंबर, 2016 को स्थानीय संत जेवियर कॉलेज रांची के सभागार में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, झारखंड राज्य के तत्वावधान में अनुसूचित जाति/जन जाति कल्याण संघ द्वारा एक दिवसीय सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से आमंत्रित झारखंड विधान सभा अध्यक्ष, डॉ. दिनेश उरांव, डॉक्टर उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष – अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, पूर्व अनुसूचित जाति/जन जाति आयोग के चेयरमैन रामेश्वर उरांव सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित हुए।

इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति/जन जाति एवं राष्ट्रीय संदर्भ में हमारी भूमिका पर जोरदार गहन मंथन किया गया। आने वाले भविष्य की ओर इंगित करते हुए एवं अपनी अस्मिता के रक्षार्थ अनुसूचित जाति/जन जाति के सदस्यों को अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

इस ओर भी प्रकाश डाला गया :–

भारत सरकार एवं यूनाइटेड बैंक सहित सभी बैंकों के भविष्य सहित कर्मियों पर प्रतिकूल आशंका व्यक्त किया गया। इस अवसर पर माननीय श्री रामेश्वर उरांव ने अनुसूचित जाति / जन जाति को एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया किया तथा प्रत्येक दिन डॉक्टर अंबेडकर एवं बिरसा के गुणों को आत्मसात करने की सलाह दिया गया।

माननीय विधान सभा अध्यक्ष, श्री दिनेश उरांव ने अपने समाज की ओर झांकते हुए कहा कि हम अपनी संस्कृति एवं अस्मिता पर गर्व तो करते हैं किंतु उसे आगे बढ़ाने का काम नहीं करते। उसे जीवंत करना होगा, बढ़ाना होगा। हम सरकार के साथ रखकर समाज हित में अच्छा कदम उठाने का हर संभव प्रयास करेगें।

माननीय डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, ने जानकारी देते हुए कहा कि एम. नागराज बनाम भारत सरकार (पदोन्नति में आरक्षण) के मामने में केन्द्र सरकार की लिचस्पी नहीं दिख रही है। इसको कायम रखने हेतु अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों को एकजुट होकर अथक संघर्ष करना होगा। न्यायपालिका खासकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा न्यायपालिका, आम जनता एवं सदस्य को गुमराह कर अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही है और पांच जजों की पंचायत में पूरे संसद को मुट्ठी में कर रखा है और मनमाने ढंग से आदेश–निर्देश दे रही है। अनुसूचित जाति / जन जाति के लोगों को एकजुट होकर अथक संघर्ष करना होगा। न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा न्यायपालिका, आम जनता एवं सदस्य को गुमराह कर अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही है और पांच जजों की पंचायत में पूरे संसद को मुट्ठी में कर रखा है और मानमाने ढंग से आदेश–निर्देश दे रही है। अनुसूचित जाति / जन जाति के लोगों को भारतीय नेताओं की कथनी एवं करनी पर अफसोस प्रकट करते हुए कहा कि बिना आपके संघर्ष प्रयास के वे कुछ नहीं देने वाले हैं। झारखंड मसले पर सीएनटी एवं एसपीटी के मामले में कहा कि इससे जमीन की लूट बढ़ जाएगी। अनुसूचित जाति/जन जाति के लोग अपनी संपदा से बेदखल हो जाएंगें।

अतः राज्य सरकार को इस दिशा में हितकारी कदम/संशोधन करने की आवश्यकता है। परिसंघ के प्रदेश महासचिव श्री मधुसूदन कुमार ने कहा कि जब तक सरकारी विभाग लोक उपक्रम है। हमारी आरक्षण रहते हुए भी हम खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। सरकारी विभागों / उपक्रमों को प्रतिदिन साजिश के तहत ध्वस्त किया जा रहा है। निवेश, निजीकरण एवं ठेकेदारी प्रथा में डाली जा रही है। जहां हमारी रोजगार की संभावना थी उसे नष्ट कर हमारी पीढ़ियों को सिर्फ मजदूर बनाकर रखने का षड्यंत्र चल रहा है।

अतः राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में हमें भारत के औद्योगीकरण, मंदिरों को बचाना होगा। इस अवसर पर अनेकों प्रबुद्ध जनों ने अपनी–अपनी बातों को रखा। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री नीतिरेन टोपो, महासचिव श्री बलिराम राम एवं विनय मुंडू का सक्रिय सहयोग रहा एवं इसके साथ झारखंड प्रदेश परिसंघ का संपूर्ण सहयोग रहा। श्री बलिराम ने प्रदेश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधि एवं सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया।

मधुसूदन कुमार
महासचिव, झारखंड परिसंघ

भूमि के मालिकाना हक के लिए परिसंघ का प्रतिनिधिमंडल ग्रामीण विकास मंत्री से मिला

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर। डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के नेतृत्व में दिल्ली देहात परिसंघ इकाई के पदाधिकारियों ने भारत के ग्रामीण विकास मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट की। पिछले 46 वर्षो से 20 सुत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत (दिल्ली लैंड रिफार्म ऐक्ट 1954) के नियम के अनुसार सन् 1970–1976 में दिल्ली देहात के अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व कमजोर वर्गो में कृषि योग्य भूमि का मालिकाना अधिकार आज तक नहीं मिला। जबकि दिल्ली सरकार मई, 2012 में इस प्रस्ताव को पास करके भारत सरकार की अनुमति के लिए चार वर्ष पूर्व भेज चुकी है। डॉ. उदित राज सांसद (लोकसभा) एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के नेतृत्व में दिल्ली देहात परिसंघ इकाई के पदाधिकारियों ने उपरोक्त विषय पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति, भारत सरकार के गृह मंत्री, दिल्ली के मुख्य मंत्री से समय-समय पर मुलाक़ात कर कृषि योग्य भूमि का मालिकाना हक़ देने का अनुरोध किया था। आज इस विषय पर भारत के ग्रामीण विकास मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डॉ. उदित राज, सांसद को आश्वाशन दिया कि इस विषय पर जल्द ही महत्वपूर्ण फैसला करके देहात के दलित किसानों को मालिकाना हक़ दिया जाएगा।

माननीय डॉ. उदित राज सांसद लोकसभा के नेवृत्व में दिल्ली देहात परिसंघ इकाई के प्रदेश अध्यक्ष श्री सत्यानारायन, महासचिव श्री अशोक अहलावत, उपाध्यक्ष व संयोजक श्री सतबीर सिंह, कोषाध्यक्ष श्री मंगत राम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री स्वरूप सिंह, सचिव श्री टेक चंद व उपाध्यक्ष मंगत राम पहलवान ने भेंट की।

– सत्यानारायन
प्रदेश अध्यक्ष
दिल्ली देहात – अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ

Socialism for the Rich, Capitalism for the Poor: An Interview With Noam Chomsky

By C. J. Polychroniou

How did we reach a historically unprecedented level of inequality in the United States? A new documentary, Requiem for The American Dream, turns to the ever-insightful Noam Chomsky for a detailed explanation of how so much wealth and power came to be concentrated in so few hands. Click here to order this DVD by making a donation to Truthout today!

The United States is rapidly declining on numerous fronts -- collapsing infrastructure, a huge gap between haves and have-nots, stagnant wages, high infant mortality rates, the highest incarceration rate in the world -- and it continues to be the only country in the advanced world without a universal health care system. Thus, questions about the nature of the US's economy and its dysfunctional political system are more critical than ever, including questions about the status of the so-called American Dream, which has long served as an inspiration point for Americans and prospective immigrants alike. Indeed, in a recent documentary, Noam Chomsky, long considered one of America's voices of conscience and one of the world's leading public intellectuals, spoke of the end of the American Dream. In this exclusive interview for Truthout, Chomsky discusses some of the problems facing the United States today, and whether the American Dream is "dead" -- if it ever existed in the first place.

C.J. Polychroniou: Noam, in several of your writings you question the usual view of the United States as an archetypical capitalist economy. Please explain.

Noam Chomsky: Consider this: Every time there is a crisis, the taxpayer is called on to bail out the banks and the major financial institutions. If you had a real capitalist economy in place, that would not be happening. Capitalists who made risky investments and failed would be wiped out. But the rich and powerful do not want a capitalist system. They want to be able to run the nanny state so when they are in trouble the taxpayer will bail them out. The conventional phrase is "too big to fail."

The IMF did an interesting study a few years ago on profits of the big US banks. It attributed most of them to the many advantages that come from the implicit government insurance policy -- not just the featured bailouts, but access to cheap credit and much else -- including things the IMF researchers didn't consider, like the incentive to undertake risky transactions, hence highly profitable in the short term, and if anything goes wrong, there's always the taxpayer. Bloomberg Businessweek estimated the implicit taxpayer subsidy at over $80 billion per year.

Much has been said and written about economic inequality. Is economic inequality in the contemporary capitalist era very different from what it was in other post-slavery periods of American history?

The inequality in the contemporary period is almost unprecedented. If you look at total inequality, it ranks amongst the worse periods of American history. However, if you look at inequality more closely, you see that it comes from wealth that is in the hands of a tiny sector of the population. There were periods of American history, such as during the Gilded Age in the 1920s and the roaring 1990s, when something similar was going on. But the current period is extreme because inequality comes from super wealth. Literally, the top one-tenth of a percent are just super wealthy. This is not only extremely unjust in itself, but represents a development that has corrosive effects on democracy and on the vision of a decent society.

What does all this mean in terms of the American Dream? Is it dead?

The "American Dream" was all about class mobility. You were born poor, but could get out of poverty through hard work and provide a better future for your children. It was possible for [some workers] to find a decent-paying job, buy a home, a car and pay for a kid's education. It's all collapsed -- and we shouldn't have too many illusions about when it was partially real. Today social mobility in the US is below other rich societies.

Is the US then a democracy in name only?

The US professes to be a democracy, but it has clearly become something of a plutocracy, although it is still an open and free society by comparative standards. But let's be clear about what democracy means. In a democracy, the public influences policy and then the government carries out actions determined by the public. For the most part, the US government carries out actions that benefit corporate and financial interests. It is also important to understand that privileged and powerful sectors in society have never liked democracy, for good reasons. Democracy places power in the hands of the population and takes it away from them. In fact, the privileged and powerful classes of this country have always sought to find ways to limit power from being placed in the hands of the general population -- and they are breaking no new ground in this regard.

Concentration of wealth yields to concentration of power. I think this is an undeniable fact. And since capitalism always leads in the end to concentration of wealth, doesn't it follow that capitalism is antithetical to democracy?

Concentration of wealth leads naturally to concentration of power, which in turn translates to legislation favoring the interests of the rich and powerful and thereby increasing even further the concentration of power and wealth. Various political measures, such as fiscal policy, deregulation, and rules for corporate governance are designed to increase the concentration of wealth and power. And that's what we've been seeing during the neoliberal era. It is a vicious cycle in constant progress. The state is there to provide security and support to the interests of the privileged and powerful sectors in society while the rest of the population is left to experience the brutal reality of capitalism. Socialism for the rich, capitalism for the poor.

So, yes, in that sense capitalism actually works to undermine democracy. But what has just been described -- that is, the vicious cycle of concentration of power and wealth -- is so traditional that it is even described by Adam Smith in 1776. He says in his famous Wealth of Nations that, in England, the people who own society, in his days the merchants and the manufacturers, are "the principal architects of policy." And they make sure that their interests are very well cared for, however grievous the impact of the policies they advocate and implement through government is on the people of England or others.

Now, it's not merchants and manufacturers who own society and dictate policy. It is financial institutions and multinational corporations. Today they are the groups that Adam Smith called the masters of mankind. And they are following the same vile maxim that he formulated: All for ourselves and nothing for anyone else. They will pursue policies that benefit them and harm everyone else because capitalist interests dictate that they do so. It's in the nature of the system. And in the absence of a general, popular reaction, that's pretty much all you will get.

Let's return to the idea of the American Dream and talk about the origins of the American political system. I mean, it was never intended to be a democracy (actually the term always used to describe the architecture of the American political system was "republic," which is very different from a democracy, as the ancient Romans well understood), and there had always been a struggle for freedom and democracy from below, which continues to this day. In this context, wasn't the American Dream built at least partly on a myth?

Sure. Right through American history, there's been an ongoing clash between pressure for more freedom and democracy coming from below and efforts at elite control and domination from above. It goes back to the founding of the country, as you pointed out. The "founding fathers," even James Madison, the main framer, who was as much a believer in democracy as any other leading political figure in those days, felt that the United States political system should be in the hands of the wealthy because the wealthy are the "more responsible set of men." And, thus, the structure of the formal constitutional system placed more power in the hands of the Senate, which was not elected in those days. It was selected from the wealthy men who, as Madison put it, had sympathy for the owners of wealth and private property.

This is clear when you read the debates of the Constitutional Convention. As Madison said, a major concern of the political order has to be "to protect the minority of the opulent against the majority." And he had arguments. If everyone had a vote freely, he said, the majority of the poor would get together and they would organize to take away the property of the rich. That, he added, would be obviously unjust, so the constitutional system had to be set up to prevent democracy.

Recall that Aristotle had said something similar in his Politics. Of all political systems, he felt that democracy was the best. But he saw the same problem that Madison saw in a true democracy, which is that the poor might organize to take away the property of the rich. The solution that he proposed, however, was something like a welfare state with the aim of reducing economic inequality. The other alternative, pursued by the "founding fathers," is to reduce democracy.

Now, the so-called American Dream was always based partly in myth and partly in reality. From the early 19th century onward and up until fairly recently, working-class people, including immigrants, had expectations that their lives would improve in American society through hard work. And that was partly true, although it did not apply for the most part to African Americans and women until much later. This no longer seems to be the case. Stagnating incomes, declining living standards, outrageous student debt levels, and hard-to-come-by decent-paying jobs have created a sense of hopelessness among many Americans, who are beginning to look with certain nostalgia toward the past. This explains, to a great extent, the rise of the likes of Donald Trump and the appeal among the youth of the political message of someone like Bernie Sanders.

After World War II, and pretty much up until the mid-1970s, there was a movement in the US in the direction of a more egalitarian society and toward greater freedom, in spite of great resistance and oppression from the elite and various government agencies. What happened afterward that rolled back the economic progress of the post-war era, creating in the process a new socio-economic order that has come to be identified as that of neoliberalism?

(Contd. on page 7)

Scattered and invisible

Non-Jatav Dalits in UP do not find political representation because of their limited role in swaying state and national elections.

Badri Narayan

The media and political analysts discuss the possibility of the success or failure of any political party on the basis of the numerical percentage of its core voters. Statistical analysis looks at these castes and communities as a homogeneous vote bank, but in reality they are not so. The deep-rooted desire for recognition and the aspiration for political participation lure the numerically large and influential castes among Dalits and backwards to vote in favour of a particular political party. Even among these social groups, the most marginalised — which are scattered and numerically less — follow a different voting pattern.

Dalits, who comprise about 21.6 per cent of the population of Uttar Pradesh, are widely considered to form the base of the Bahujan Samaj Party (BSP). On analysing the grassroot reality, we find that among the large number of Dalit castes, it is only the Jatavs who are the core voters for BSP. In addition, castes like Pasi, Dhobhi, Kori, Khatik are considered the "Bahujan voters" of the party. Among the 65 Dalit castes, more than 55 are numerically less, scattered and their presence is almost negligible. A few of them are Basor, Sapera, Kuchbadhiya, Musahar, Begaar, Tantwa, Rangrej and Sarvan. At the local level, these communities often vote under the influence of prominent Dalit, backward and savarna castes. Political parties are either unaware of their presence or do not give them much importance as they make a weak vote bank.

These numerically small castes mostly reside in hamlets comprising of 10 or 20 huts and even in large, multi-caste hamlets only two or three of their huts can be seen. Though their votes are given due importance in the panchayat elections, the same is not true during Lok Sabha and Vidhan Sabha elections. Even political parties like the BSP, which are actively involved in Dalit-Bahujan politics, take them for granted. Neither do candidates from these castes get tickets during elections nor are they provided political participation. Thus, we see such castes living in penury and existing as an invisible social group in Indian democratic politics. It is sad that even after seven decades of Independence they have not been able to become a part of our political society or received any recognition as subaltern citizens.

Though they come under the category of Dalit and Bahujan, their presence is almost negligible in Dalit and Bahujan politics. They get a minor share of the resources distributed to the poor and the marginalised. These castes do not possess their own community leaders and the political parties too are hesitant in giving them leadership roles. They are still far away from the doors of education and are economically weak to the extent that they are not able to develop their own politics. They can develop their own politics only when an economically strong group emerges from amongst their communities.

The RSS has begun some work among these groups in certain regions of UP. The Sangh is actively propagating its samrasta (harmony) programmes in villages at the border areas of UP and Nepal which extends from Gorakhpur to Bahraich, the Awadh region and some areas of eastern UP. The Sangh is organising programmes like the cleanliness of hamlets, having samrasta bhoj with residents and is also running primary schools. It is also running its shakhas in the gardens and ponds near the hamlets of marginalised Dalits and is endeavouring to produce activists from among them.

The Sangh's work in this direction may produce activists who can take on leadership roles, but it is quite difficult to say the number of years it will take for these marginalised communities to create a place in the BJP's politics. During my field visits, I observed that in the executive training camps organised in the areas adjoining Allahabad, the RSS is making efforts to establish a connection with the activists from the "small" Dalit castes.

The Congress is also showing an interest in associating with these castes and would like to provide political representation to the non-Jatav Dalit castes. But on coming to terms with the limited vote-share and probability of candidates from these castes winning, it may limit their political participation. The local Congress leadership is keen to get non-Jatav Dalits as voters, but they do not have a long-term policy to establish leaders from among these communities or to provide them any political recognition. BSP leaders show a keen interest is associating such castes with their party and consider them a part of the Bahujan society, yet they have done little for the political inclusion of these communities.

A major irony of Indian democratic politics is that the political value of a citizen is determined by the numerical strength of his/her caste and her/his efficiency in terms of the money and power to achieve victory during elections. Democracy has become a game in the hands of various powerful people and communities. Kanshi Ram laid the foundation of the Bahujan political structure based on the principle that "the political participation of any caste is directly proportional to its numerical strength". Based on this principle, numerically strong Dalit castes have received political visibility and political participation — to some extent — after the development of Bahujan politics. But the fate of more than 55 Dalit and Bahujan castes, scattered in various pockets of Uttar Pradesh, is yet to be decided. This is a crucial question before our democracy, the answer for which must be found sooner rather than later.

The writer is a social scientist and author. His latest book, 'Fractured Tales:Invisibles in Indian Democracy', is published by Oxford University Press

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/non-jatav-dalits-voters-uttar-pradesh-elections-scattered-bsp-4427206/

Socialism for the Rich, Capitalism ...

(Contd. from page 6)

Beginning in the 1970s, partly because of the economic crisis that erupted in the early years of that decade and the decline in the rate of profit, but also partly because of the view that democracy had become too widespread, an enormous, concentrated, coordinated business offensive was begun to try to beat back the egalitarian efforts of the post-war era, which only intensified as time went on. The economy itself shifted to financialization. Financial institutions expanded enormously. By 2007, right before the crash for which they had considerable responsibility, financial institutions accounted for a stunning 40 percent of corporate profit. A vicious cycle between concentrated capital and politics accelerated, while increasingly, wealth concentrated in the financial sector. Politicians, faced with the rising cost of campaigns, were driven ever deeper into the pockets of wealthy backers. And politicians rewarded them by pushing policies favorable to Wall Street and other powerful business interests. Throughout this period, we have a renewed form of class warfare directed by the business class against the working people and the poor, along with a conscious attempt to roll back the gains of the previous decades.

Now that Trump is the president-elect, is the Bernie Sanders political revolution over?

That's up to us and others to determine. The Sanders "political revolution" was quite a remarkable phenomenon. I was certainly surprised, and pleased. But we should remember that the term "revolution" is somewhat misleading. Sanders is an honest and committed New Dealer. His policies would not have surprised Eisenhower very much. The fact that he's considered "radical" tells us how far the elite political spectrum has shifted to the right during the neoliberal period. There have been some promising offshoots of the Sanders mobilization, like the Brand New Congress movement and several others.

There could, and should, also be efforts to develop a genuine independent left party, one that doesn't just show up every four years but is working constantly at the grassroots, both at the electoral level (everything from school boards to town meetings to state legislatures and on up) and in all the other ways that can be pursued. There are plenty of opportunities -- and the stakes are substantial, particularly when we turn attention to the two enormous shadows that hover over everything: nuclear war and environmental catastrophe, both ominous, demanding urgent action.

http://www.truth-out.org/opinion/item/38682-socialism-for-the-rich-capitalism-for-the-poor-an-interview-with-noam-chomsky

---

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 20 ● Issue 3 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 16 to 31 December, 2016

Dr. Udit Raj tweets asking for reservation in cricket

Talks about Vinod Kambli as a prime example of discrimination

New Delhi, 28th December : Dr. Udit Raj, National Chairman, All India Confederation of SC/ST Organisations today asked for reservation in the Indian cricket team for SC/STs. Dr. Udit Raj said that Dalits have a right to be a part of Indian cricket, and their inclusion will help India create the best team in the world. Dr. Udit Raj also gave an example of reservation in the South African cricket team to justify this demand. He said that in the South African cricket team, there is a provision of having more than half blacks in the team to remove colour based discrimination in sports.

While selecting the state cricket team for Jammu and Kashmir, it is ensured that out of the 16 players, 7 players belong to Jammu and 9 to Kashmir, or that 7 belong to Kashmir and 9 to Jammu. There is no such provision for the Indian cricket team. All players can even be selected from one city. Due to this, players from other regions do no get a chance to play for India.

Vinod Kambli has himself said that he was a victim of discrimination. Today, he should not back down from his earlier statement, but should come out even stronger. He should fight not only for his self - respect, but also for the scores who dream of playing for the Indian cricket team. This fight is not his alone, but of all the Dalits in the country. If he had stuck to his stand, then perhaps what happened to him would not have happened to other Dalit youth in the country.

It is surprising to learn that Vinod Kambli, a childhood friend and teammate of Sachin Tendulkar, was considered to be of the same class as the master blaster. He had an explosive start to his career, but soon got lost in the glamour and glitz associated with the game at the national level. Born in 1971 in Mumbai, Vinod Ganpat Kamble debuted in one day internationals in 1991 and in test cricket in 1993. In 2009, he declared his retirement from international cricket. In 17 test matches, his average was 54.20 and highest score 227. He made a total of 4 centuries in his test career. In one day cricket, he played 104 matches and scored 2477 runs in 97 innings at an average of 32.59. He also scored 2 centuries in one day cricket.

Despite a comparatively poorer performance, Sachin Tendulkar's son Arjun Tendulkar was selected for the West Zone in the under - 16 team for the regional tournament held in Hubli in May 2016. Pranav Dhawane, a Dalit player who scored 1000 runs in one innings was discriminated against and not selected for the team, despite his performance having been appreciated by several stalwarts of the game, including Sachin Tendulkar. Pranav's father is an auto rickshaw driver. Samir Dighe was a part of the selection committee which selected the under - 16 team, is known to be close to Sachin Tendulkar and amongst one of his countless well wishers.

According to the recently published Thorat committee report, there is massive discrimination against Dalit players in sports as well, apart from other areas. According to the report, Dalits sometimes get an opportunity in games which require massive physical effort, such as football and volleyball, also because such sports do not get much media and societal coverage. Sports such as cricket and hockey which are covered much more by the media are areas of peak discrimination and Dalits almost never get a chance to participate in them.

Dr. Udit Raj said that that the Confederation is the largest umbrella organisation of SC/STs throughout the country. He said that many players approach him for support, and most of them are also recommended by him, but they are usually not selected. Dr. Raj said that he is thinking about quota in sports so that this discrimination can be stopped. There are many able, talented players amongst Dalits, but there is no guarantee that they would be selected and give a chance to represent the country. Vinod Kambli is one such example of this. Dr. Raj said that he is of the opinion that it will be beneficial for the country if talent is searched for amongst 35 crore Dalits.

Today, the country talks about equality, but Dalits still face inequality and lack of access of opportunities; whether it be in employment, education, business or in the field of sports. People believe that only talented players get an opportunity to play in the cricket team, then why should there be reservation in cricket? No one is ready to answer as to why talented players are born into Brahmin and higher caste families. If we talk about the current team, then only 4% Brahmins have produced 70% of the talented players who are a part of the team. Other than them, only Jats, Sikh, Muslims and other castes are selected in the team. Why are Dalits completely absent from the team? In the last 80 years, only 2 Dalits have been selected in the cricket team - Balwant Palu from Karnataka and Vinod Kambli from Mumbai. Are talented players not born into Dalit families? If we talk about Balwant Palu, despite fantastic scores, he was sidelined and not made the captain of the team because he was a Dalit; a similar situation is also observed in case of Vinod Kambli. Aside from the general public, even cricket experts believe that Vinod Kambli was more talented than Sachin Tendulkar, and even the statistics of his short career attest to this. His average in test cricket was over 50, due to which he was being compared to other cricketing greats. Kambli never got sufficient opportunities and this star, which had a bright future, was never allowed to emerge. Dr. Udit Raj also extorted Dalits to come together and fight for cases as seen in the case of Vinod Kambli, instead of remaining mute spectators and bystanders to the suffering and discrimination suffered by Dalits.

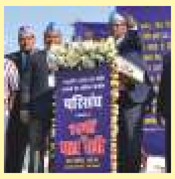

All India Parisangh
@ AIParisangh
@Dr_Uditraj triggers row,
balames kambli's 'Dalit' orgin
for his 'exclusion from cricket'
m.indiatoday.instory/bjp-mp-u...

RESERVATION IN CRICKET
" We don't want any Eklavya suffering again because of Arjun."

28/12/2016, 9:20 PM

Dr. Udit Raj, MP @Dr_uditraj
20 July 2009 @vinodkambli349
asserted that injustices had been
done to him he proved selectors
wrong with his scores & by
coming back in time

Vinod Kambli @vinodkambli...
"Mr. Raj, I don't support any of
your statements. Hence, I request
you to refrain from using my name

Dr. Udit Raj, MP @Dr_uditraj
@vinodkambli349 you should
not be shy of accepting that u r
a Dalit and that was the reason
of ur exclusion from cricket
@BCCI @AIParisangh

Vikas Mogha @vikasmogha
@Dr_Uditraj @vinodkambli349
विनोद कांबली जी शिक्षित इलीट क्लास है,
यह वास्तविकता का साथ दे और अपने
बयान पर कायम रहे तो देश बदल
सकता है।

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place,
New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya